

उत्तराखण्ड सरकार,  
न्याय अनुभाग-1

संख्या : 161/XXXVI(1)/07/306-एक(1)/2005  
देहरादून: 24 अप्रैल, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान सभी नियमों और आदेशों को अतिक्रमित करते हुए, उत्तराखण्ड में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों और कुटुम्ब न्यायालयों के लिपिकवर्गीय अधिष्ठान के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 2007

1- संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार :

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 2007' है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह नियमावली उत्तराखण्ड राज्य में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों और कुटुम्ब न्यायालयों के लिपिकवर्गीय अधिष्ठान के सभी व्यक्तियों पर लागू होगी।

2- परिभाषाएं : जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य जिला एवं सेशन न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय से है,
- (ख) "मुख्य न्यायाधीश" से तात्पर्य उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है,
- (ग) "आयोग" से तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से है,

- (घ) "संविधान" से तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,
- (ङ) "न्यायालय" से तात्पर्य उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से है,
- (च) "कुटुम्ब न्यायालय" से तात्पर्य प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय और अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय से है,
- (छ) "सरकार" से तात्पर्य उत्तराखण्ड की सरकार से है,
- (ज) "राज्यपाल" से तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है,
- (झ) "लिपिकवर्गीय अधिष्ठान" से तात्पर्य अधीनस्थ सिविल न्यायालयों और कुटुम्ब न्यायालयों के लिपिकवर्गीय सेवकों से है।
- (ट) "अधीनस्थ सिविल न्यायालय" से तात्पर्य उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अपर सिविल जज, (सीनियर डिवीजन), सहायक सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रिलवे), न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय और अपर न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय से हैं,
- (ठ) "भर्ती का वर्ष" से तात्पर्य उस कलैण्डर वर्ष की पहली जनवरी से, जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाय, प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

3- सेवा का संवर्ग :

लिपिकवर्गीय सेवा, उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में जजशिप और कुटुम्ब न्यायालयों में नियोजित कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्ग और प्रवर्गों से मिलकर बनेगी :-

सिविल न्यायालय

<u>क्र०सं०</u>	<u>पद नाम</u>	<u>वेतनमान</u>	<u>भर्ती का स्रोत</u>
(क)	प्रतिलिपिक/ कनिष्ठ लिपिक/ सहायक लेखा लिपिक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, लेखन सामग्री लिपिक, अमीन श्रेणी-2, सहायक अभिलेखपाल, सहायक नाजिर	रु० 3050-4590 या सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः नियत वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा या समूह 'घ' के नियमित कर्मचारियों में से, जो तत्समय प्रवृत्त नियमावली/ शासनादेशों के अनुसार शर्तें पूरी करते हों, ऐसे शासनादेशों में नियत कोटा के भीतर, चयन द्वारा
(ख)	वाद लिपिक/ निष्पादन लिपिक, अहलमद, उप नाजिर, लेखा लिपिक, सेशन लिपिक, अपील लिपिक, खजांची, विविध लिपिक, सिविल जज (एस.डी.), सिविल जज (जे.डी.) और न्यायिक मजिस्ट्रेट के मुंसरिम, पेशकार, पुस्तकालयाध्यक्ष, अमीन श्रेणी-1, उप-अभिलेखपाल	रु० 4000-6000 या सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (क) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्हें तीन वर्ष का अनुभव हो।

(ग)	जिला न्यायाधीश / अपर जिला न्यायाधीश / सी.जे.एम. /अपर सी.जे.एम., न्यायालयों के मुंसरिम, पेशकार, सेंट्रल नाजिर, अभिलेखपाल, प्रधान प्रतिलिपिक, द्वितीय लिपिक	रु0 4500—7000 या सरकार द्वारा समय—समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (ख) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्हें तीन वर्ष का अनुभव हो
(घ)	सदर मुंसरिम	रु0 5500—9000 या सरकार द्वारा समय—समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (ग) में से प्रोन्नति या चयन द्वारा, जिसने कुल मिलाकर कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
(ङ.)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रु0 6500—10500 या सरकार द्वारा समय—समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (ग) और प्रवर्ग (घ) में से प्रोन्नति या चयन द्वारा, जिसने कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
(च)	सिविल जज (जे.डी.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (एस. डी.) / अपर सिविल जज (एस.डी.) के न्यायालयों में आशुलिपिक श्रेणी—1	रु0 4000—6000 या सरकार द्वारा समय—समय पर पुनः नियत वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा

(छ)	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों में वैयक्तिक सहायक	रु0 5500-9000 या सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (च) में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्हें पांच वर्ष का अनुभव है।
(ज)	जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों में वैयक्तिक सहायक	रु0 6500-10,500 या सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रवर्ग (च) में से प्रोन्नति द्वारा

उपखंड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित प्रवर्गों से एक संवर्ग और प्रवर्ग (च) से (ज) तक में उल्लिखित प्रवर्गों से दूसरा संवर्ग बनेगा।

#### कुटुम्ब न्यायालय

क0सं0	पद का नाम	वेतनमान	भर्ती का श्रोत
(क)	टंकक-सह-प्रतिलिपिक	रु0 3050-4590 या सरकार द्वारा पुनः नियत वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा
(ख)	सहायक लेखाकार/ निष्पादन लिपिक-सह-संरक्षण लिपिक, वाद लिपिक-सह-अनुरक्षण लिपिक	रु0 4000-6000 या सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रोन्नति से या जजशिप से प्रतिनियुक्ति द्वारा
(ग)	पेशकार	रु0 4500-7000 या सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रोन्नति या जजशिप से प्रतिनियुक्ति द्वारा
(घ)	वैयक्तिक सहायक	रु0 5500-9000 या सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः नियत वेतनमान	सीधी भर्ती या जजशिप से प्रतिनियुक्ति द्वारा



(ड)	सदर मुंसरिम	रु0 5500—9000 या सरकार द्वारा समय—समय पर पुनः नियत वेतनमान	प्रोन्नति से या जजशिप से प्रतिनियुक्ति द्वारा
-----	-------------	--	--

4— अधिष्ठान की स्वीकृत संख्या :

जजशिप या कुटुम्ब न्यायालय के लिपिकवर्गीय अधिष्ठान की संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाए।

5— राष्ट्रीयता :

किसी व्यक्ति को लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा, जबकि वह भारत का नागरिक हो और आयोग द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन से पूर्व उत्तराखण्ड के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

6— शैक्षिक अर्हता :

लिपिकीय पद

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो।

(ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी में टंकण का, कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 40 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो।

(घ) कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

आशुलिपिक एवं कुटुम्ब न्यायालय के वैयक्तिक सहायक

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो।

(ख) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी आशुलेखन में कमशः 80 शब्द एवं 100 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 60 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।

(घ) कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान।

7- आयु :

लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जनवरी को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

परन्तु मुख्य न्यायाधीश लोक हित में अथवा उचित व्यवहार के आधार पर किसी अभ्यर्थी के पक्ष में आयु सीमा बढ़ा सकेंगे।

8- चरित्र :

लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। अभ्यर्थी को यथास्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या स्कूल के, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधान अधिकारी और दो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों से (जो नातेदार न हों), जो उसके निजी जीवन से सुपरिचित हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में किसी पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

9- शारीरिक स्वस्थता :

किसी भी ऐसे व्यक्ति को लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

किसी अभ्यर्थी को लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में नियुक्त किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैंड बुक, खंड-दो, भाग 3 के अध्याय-तीन में दिए गए फंडामेंटल रूल 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

10- अनुसूचित जाति, आदि के लिए पदों का आरक्षण :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

11- महिलाओं की पात्रता :

महिलाएं भी प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में नियुक्ति के लिए पात्र होंगी।

12- वैवाहिक प्रास्थिति :

लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो।



13- लिपिकवर्गीय अधिष्ठान में सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया :

रिक्तियों का अवधारण :-

- (क) उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिला न्यायाधीश और कुटुम्ब न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश भर्ती के वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संभावित संख्या और नियम 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।
- (ख) रिक्तियां अधिसूचित और न्यायालय को सूचित की जाएंगी।
- (ग) जिला न्यायाधीशों और कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा इस प्रकार अधिसूचित रिक्तियां समेकित कर न्यायालय, आयोग को अधिसूचित करेगा।
- (घ) प्रतियोगितात्मक परीक्षा :  
प्रतियोगितात्मक परीक्षा ऐसे समय और ऐसी तिथियों में आयोजित की जाएंगी जो आयोग द्वारा अधिसूचित की जाएं।
- (ङ) आवेदन पत्र :
  - (1) प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र, आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों में प्रकाशित कर आमंत्रित किए जाएंगे।
  - (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र का धारक न हो।

- (3) फीस : अभ्यर्थी, आयोग को ऐसी फीस का संदाय करेंगे जो समय-समय पर सरकार या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। फीस की वापसी का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- (4) यदि आवेदकों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित रिक्तियों से बहुत अधिक है तो आयोग अपने द्वारा विहित रीति से प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा ले सकेगा और प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त अंक, प्रवीणता का कम अवधारित करने के लिए गणना में नहीं लिए जाएंगे।
- (5) पाठ्यक्रम : आयोग द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षा, परिशिष्ट-I में दिए गए पाठ्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी।
- (6) पक्ष समर्थन : इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति हेतु अनर्ह कर देगा।
- (7) लिखित परीक्षा के परिणाम तैयार कर लेने के पश्चात् आयोग, ऐसी संख्या में उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जिन्होंने आयोग की राय में उतने न्यूनतम अंक प्राप्त कर लिये हैं जो आयोग नियत करे।
- (8) इस नियमावली या किसी अन्य आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी आयोग, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी व्यक्ति या न्यायालय के अधिकारी को उपनियम (7) के अन्तर्गत बुलाए गए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा और अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के बारे में उसके द्वारा दी गई राय की उपेक्षा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसकी राय अस्वीकार करने के लिए प्रबल और ठोस कारण न हों और

इस हेतु आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण उल्लिखित किए जायेंगे।

14- आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची :

- (1) इसके उपरान्त आयोग, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में दिये गये अंकों के कुल योग के आधार पर उनकी श्रेष्ठता के क्रम में चयन सूची तैयार करेगा ;

परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हों तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा ;

परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थी, जो समान आयु के हों, बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उस अभ्यर्थी का नाम, जिसने लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हैं, चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

- (2) चयन सूची को आयोग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा।

15- अधिष्ठान में नियुक्ति :

- (1) आयोग द्वारा नियम 14 के अधीन इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची (श्रेष्ठता सूची) जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में अभिप्राप्त कुल अंकों का उल्लेख किया जाएगा, न्यायालय को अग्रसारित की जायेगी।
- (2) न्यायालय अभ्यर्थियों के नाम जजशिप और कुटुंब न्यायालयों में रिक्तियों के अनुसार श्रेष्ठता के सही क्रम में जिला न्यायाधीशों और कुटुम्ब न्यायालयों को भेजेगा। अपनी इच्छा के जिले में तैनाती के लिए किसी अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (3) चयन सूची, मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।

- (4) जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय उन अभ्यर्थियों की, जिनके नाम न्यायालय द्वारा भेजे जाते हैं, सरकारी अधिसूचना और आदेशों में उपबन्धित रोस्टर के अनुसार, नियुक्तियां करेंगे।

16- चयनित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रीकरण :

- (1) जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के नाम, परिशिष्ट-II में विहित प्रारूप में, एक जिल्द बन्द रजिस्टर में श्रेष्ठता के क्रम में प्रविष्ट किये जाएंगे और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियों के मूल प्रमाण-पत्रों के निरीक्षण के पश्चात् प्रत्येक प्रविष्टि पर यथास्थिति, जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा, तारीख सहित हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- (2) उप नियम (1) के अधीन प्रविष्ट किसी अभ्यर्थी का नाम, एक वर्ष के भीतर अकुशलता या कदाचार के लिए, बिना कोई विभागीय जाँच किये हटाया जा सकेगा।
- (3) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी को भर्ती की तारीख से एक वर्ष के भीतर नियुक्त नहीं किया जाता है तो आयोग द्वारा इस प्रकार संस्तुत की गयी सूची व्यपगत हो जायेगी। इस प्रकार संस्तुत किया गया अभ्यर्थी अधीनस्थ सिविल न्यायालयों या कुटुंब न्यायालयों के अधिष्ठान में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है :

परन्तु इस नियमावली के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या इस नियमावली से अन्यथा की गई नियुक्ति या इस नियमावली के अधीन तात्पर्यित नियुक्ति से व्यथित किसी व्यक्ति को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा।



17— परिवीक्षा :

- (1) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा :

परन्तु जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, यथास्थिति, स्वविवेक पर परिवीक्षा की अवधि छः मास की अवधि के लिए बढ़ा सकेंगे।

- (2) परिवीक्षा की अवधि की गणना पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से की जायेगी।

स्पष्टीकरण— लिपिकवर्गीय अधेष्ठान में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्ति भी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है, या वह अन्यथा सन्तुष्टि प्रदान करने में असफल रहा है, तो नियुक्ति प्राधिकारी कोई सूचना दिये बिना उसे उसके मूल पद पर, यदि वह ऐसा पद धारण करता है, प्रत्यावर्तित कर सकेंगे या कोई अन्य उपयुक्त आदेश कर सकेंगे।

18— स्थायीकरण :

पूर्ववर्ती नियम के उपबन्ध के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी पद के विरुद्ध स्थायी किया जायेगा।

19— ज्येष्ठता :

मौलिक रूप से सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

20- प्रोन्नति :

- (1) जजशिप या कुटुंब न्यायालय में उच्चतर पद, उस जजशिप या कुटुंब न्यायालय में लिपिकों के लिए आरक्षित होगा और उच्चतर पदों पर प्रोन्नति उनमें से ही की जायेगी।
- (2) अमीनों के मामलों के सिवाय प्रोन्नति, दक्षता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।
- (3) उप नियम (2) में उल्लिखित पदों से भिन्न पद, चयन पदों के रूप में माने जाएंगे, जिन पर प्रोन्नति ज्येष्ठता को सम्यकतः ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठता के आधार पर, यथास्थिति, जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा विहित उपयुक्तता परीक्षण पर आधारित होगी।
- (4) परिपत्रों, साधारण (सिविल और दाण्डिक) नियमों, फाइनेन्शियल हैंड बुक का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की प्रोन्नति जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा यथाविहित उपयुक्तता परीक्षण कर लेने के पश्चात् निम्नतम श्रेणी से अगली उच्चतर श्रेणी में की जाएगी।
- (5) सदर मुंसरिम और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पद, प्रोन्नति और चयन के पद हैं। इन पदों पर प्रोन्नति उन व्यक्तियों में से की जायेगी जिन्हें जजशिप के सभी विभागों, विशेष रूप से नजारत और लेखा में कार्य करने का पर्याप्त ज्ञान हो। सदर मुंसरिम और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति करते समय जिला न्यायाधीश, अपने द्वारा विहित उपयुक्तता परीक्षण, उन व्यक्तियों में से करेगा जो इन पदों के पूर्ववर्ती निम्नतर श्रेणी में कार्य कर रहे हैं और तब श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर इन पदों पर प्रोन्नति करेगा।

ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए वैयक्तिक सहायकों में से ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी जिला न्यायाधीश द्वारा विचार किया जायेगा।

- (6) मुख्य न्यायाधीश, यदि वह उचित समझें, तो किसी जजशिप के सदस्य की सदर मुंसरिम और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर, यदि ऐसी जजशिप में रिक्ति विद्यमान है, नियुक्ति कर सकेंगे।

टिप्पणी— चयन पद पर प्रोन्नति के लिए किसी व्यक्ति को उसकी अदक्षता के कारण छोड़ते समय उसकी सेवा के पूर्व अभिलेखों पर सम्यक रूप से विचार किया जायेगा और ज्येष्ठता की तभी उपेक्षा की जाएगी जब प्रोन्नत किया जाने वाला कनिष्ठ कर्मचारी अपने ज्येष्ठों की तुलना में उत्कृष्ट श्रेष्ठता का हो।

- (7) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में अमीनों की प्रोन्नति, एक नियम के रूप में, जिला न्यायाधीश की स्थानीय अधिकारिता के भीतर सेवा की अवधि पर विचार किये बिना सामान्य अर्हताओं की श्रेष्ठता के आधार पर विचार करते हुए की जायेगी।

- (8) अधीनस्थ न्यायालयों में अमीनों के पद पर प्रोन्नति या नियुक्ति साधारणतः उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहेगी जिनके सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश का समाधान हो जाता है कि उन्हें निम्नलिखित का पर्याप्त ज्ञान है:—

(i) हिन्दी, अंग्रेजी

(ii) गणित

(iii) माप

(iv) भूमि सर्वेक्षण और नक्शे का आरम्भिक ज्ञान

(v) सिविल प्रक्रिया संहिता

(vi) अमीनों के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित साधारण नियम (सिविल)।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में जिला न्यायाधीश किसी कर्मचारी को ऐसी अर्हताओं से छूट दे सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि संबंधित कर्मचारी अन्यथा नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।

- (9) अमीन के पद पर एक बार प्रोन्नत व्यक्ति, अन्य पदों पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए ऐसी प्रोन्नति के कारण अन्य ऐसे लिपिकों पर जो अमीन के रूप में उसकी प्रोन्नति से पहले उससे ज्येष्ठ थे, ज्येष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- (10) समूह 'घ' के अर्ह कर्मचारियों में से समूह 'ग' में निम्नतम वेतनमान के पद पर नियत कोटे के भीतर प्रोन्नति के माध्यम से सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/नियमावली की शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती/नियुक्ति की जायेगी।

21- वेतनमान :

संवर्ग के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान, चाहे नियुक्ति मौलिक या स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से हों, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा स्वीकृत वेतनमान होगा।

22- परीक्षा के दौरान वेतन :

सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति का परीक्षा के दौरान वेतन उस पद का न्यूनतम वेतन होगा जिसमें उसे नियुक्त किया गया है और राज्य की सेवा में पहले से ही किसी व्यक्ति की दशा में यह वेतन ऐसा होगा जो नियम 21 में निर्दिष्ट सुसंगत नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय हो। अनुमोदित परीक्षाधीन सेवा द्वारा वेतन वृद्धियां अर्जित की जायेंगी परन्तु यदि किसी मामले में समाधानप्रद सेवा प्रदान करने में असफल रहने के कारण परीक्षा



की अवधि बढ़ायी जाती है तो ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जायेगी।

23- स्थानान्तरण :

- (1) जिला न्यायाधीश की शिकायत पर या लोक हित में, मुख्य न्यायाधीश किसी सदर मुंसरिम या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या अधिष्ठान के किसी सदस्य का एक जजशिप से दूसरी जजशिप में उसी वेतनमान में विद्यमान रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण कर सकेंगे।
- (2) जिला न्यायाधीश, अधिष्ठान के किसी सदस्य का उसी वेतनमान में उसी जिले के भीतर एक न्यायालय/कार्यालय/विभाग से दूसरे में, जैसा वह ठीक समझें, स्थानान्तरण कर सकेंगे।

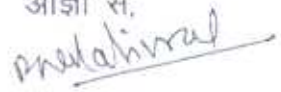
24- मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली का लागू होना :

इस नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) का अनुकूलन एवं उपान्तरण नियमावली, 2002' लिपिकवर्गीय अधिष्ठान पर लागू होगी, तदनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती की जाएगी।

25- निरसन और व्यावृत्ति :

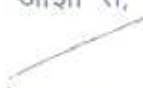
- (1) अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1947 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,
  - (क) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से ठीक पूर्व, वेतन, पेन्शन, वरिष्ठता, अनुशासनिक कार्यवाही या अन्य संबंधित प्रकरण से सम्बन्धित कोई मामला लम्बित हो, तो उसे अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1947 के अनुसार निपटाया जायेगा।

(ख) अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1947 के अधीन जारी की गई उच्च न्यायालय या राज्य सरकार की सभी अधिसूचनायें और परिपत्र, यदि कोई हैं, कमशः इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,  
  
(आर.डी.पालीवाल)  
सचिव

संख्या : 161(I) / XXXVI(1)/07 / 306-एक(1) / 2005 तददिनांक

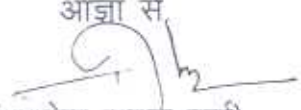
प्रतिलिपि, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 100 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
  
(आलोक कुमार वर्मा)  
अपर सचिव

संख्या : 161(II) / XXXVI(1)/07 / 306-एक(1) / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिबन्धक, मा10 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 2- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त कुटुम्ब न्यायाधीश, पौड़ी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की नैनीताल तथा उधमसिंहनगर।
- 4- सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- 5- कार्मिक अनुभाग-1 / वित्त अनुभाग-5 / एन.आई.सी. / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(आलोक कुमार वर्मा)  
अपर सचिव

परिशिष्ट-I  
(नियम 13 देखिए)


परीक्षा तीन भागों में ली जायेगी।

1-	लिखित परीक्षा	अंक
	(i) सामान्य आलेखन	(हिन्दी में) 40
	(ii) निबंध और सार लेखन	(हिन्दी में) 40
	(iii) साधारण आलेखन और सार लेखन	(अंग्रेजी में) 40
	(iv) सामान्य ज्ञान	40
2-	कम्प्यूटर पर टंकण/आशुलेखन में परीक्षण	60
	(आशुलिपिकों के लिए)	
	(i) अंग्रेजी में 60 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर पर अंग्रेजी और हिन्दी में टंकण।	
	(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी में आशुलेखन।	
	(अन्य के लिए)	
	कम्प्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी और हिन्दी में टंकण।	
3-	साक्षात्कार	
	(i) व्यक्तित्व	15
	(ii) पद विशेष के लिए ज्ञान और उपयुक्तता	15
	योग-	250

**परिशिष्ट-II**  
(नियम 16 देखिये)

भर्ती किये गये अभ्यर्थियों के रजिस्टर का प्रारूप :-

नाम	पिता का नाम	जाति, धर्म, वर्ग यदि आरक्षित वर्ग से है।	पता, अस्थायी एवं स्थायी	जन्मतिथि एवं आयु	शैक्षिक योग्यता	वर्ष एवं स्थान (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के उपरान्त)	विशेष योग्यता जैसे आशु लेखन, लेखा आदि
1	2	3	4	5	6	7	8

आज्ञा से,  
  
(आर.डी.पालीवाल)  
सचिव



In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 161/XXXVI(1)/07/306-EK(1)/2005 dated 24<sup>April</sup> 2007 for general information.

Government of Uttarakhand  
Nyay Anubhag-1  
No. 161/XXXVI(1)/07/306-EK(1)/2005,  
Dated Dehradun, 24 April, 2007.

## **NOTIFICATION**

### **Miscellaneous**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Ministerial establishment of the Civil Courts and Family Courts in the State of Uttarakhand, subordinate to the High Court.

### **THE UTTARAKHAND SUBORDINATE CIVIL COURTS MINISTERIAL ESTABLISHMENT RULES, 2007.**

#### **1. Short Title, Commencement and Extent:**

- (1) These rules may be called 'The Uttarakhand Subordinate Civil Courts Ministerial Establishment Rules, 2007.'
- (2) They shall come into force with immediate effect.

- (3) These rules shall apply to all persons in the Ministerial Establishment of the Civil Courts and Family Courts in the State of Uttarakhand, subordinate to the High Court.

**2. Definitions:** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

- (a) "Appointing authority" means the District & Sessions Judge and the Principal Judge, Family Court.
- (b) "Chief Justice" means the Chief Justice of High Court of Uttarakhand.
- (c) "Commission" means the Uttarakhand Public Service Commission.
- (d) "Constitution" means the Constitution of India.
- (e) "Court" means the High Court of Uttarakhand.
- (f) "Family Court" means the courts of Principal Judge, Family Court, Judge, Family Court and Additional Judge, Family Court.
- (g) "Government" means the Government of Uttarakhand.
- (h) "Governor" means the Governor of Uttarakhand.
- (i) "Ministerial Establishment" means the staff of the subordinate Civil Courts and Family Courts consisting of ministerial servants.
- (j) "Subordinate Civil Courts" means the Courts of District and Session Judges, Additional District and Session Judges, Civil Judges (Senior Division), Additional Civil

Judges (Senior Division), Assistant Sessions Judge, Chief Judicial Magistrates, Additional Chief Judicial Magistrates, Additional Chief Judicial Magistrates (Railway), Judicial Magistrates, Civil Judge (Junior Division), Additional Civil Judge(Junior Division) and Courts of Judge Small Cause, Additional Judge Small Cause Courts Subordinate to the High Court of Uttarakhand.

- (k) "Year of Recruitment" means a period of Twelve Months commencing from the first day of January of the calendar year in which the process of recruitment is initiated by the appointing authority.

3. **Cadre of the service:** The ministerial service shall consist of the following classes and categories of officials employed in each Judgeship and Family Courts in Uttarakhand.

### CIVIL COURTS

S.No	Name of the post	Pay scale	Source of recruitment
(a)	Copyist /Junior Clerk/Assistant Accounts Clerk, Assistant Librarian, Stationary Clerk, Amin Grade II, Assistant Record Keeper, Assistant Nazir.	Rs. 3050- 4590 or pay scale refixed by the Government from time to time	By direct recruitment or by selection from amongst the regular Group 'D' employees fulfilling conditions as per the rules / Government orders applicable not beyond the quota fixed in such Government orders.
(b)	Suits Clerk/ Execution Clerks, Ahalmads, Dy. Nazir, Accounts Clerk, Sessions Clerk, Appeals Clerk, Cashier, Misc. Clerk, Munsarim/ Readers of Civil Judge (SD) and Civil Judge (JD) / J.M., Librarian, Amin Grade I/ Deputy Record Keeper.	Rs. 4000-6000 or pay scale refixed by Government from time to time.	By promotion from amongst the category (a) having three years experience.
(c)	Munsarim / Readers of the Courts of District Judge / Addl. District Judges / C.J.M./Addl. C.J.M. Central Nazir, Record Keeper, Head Copyist, 2 <sup>nd</sup> Clerk.	Rs. 4500-7000 or pay scale refixed by Government from time to time.	By promotion from amongst the category (b) having three years experience.



- |     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| (d) | Sadar Munsarim   | Rs. 5500-9000<br>or pay scale<br>refixed by<br>Government<br>from time to<br>time.  | By promotion or<br>selection from<br>amongst the<br>category (c) who has<br>put atleast ten years<br>service in all.       |
| (e) | Senior Administrative<br>Officer   | Rs.6500-10,500<br>or pay scale<br>refixed by<br>Government<br>from time to<br>time  | By promotion or<br>selection from<br>amongst the<br>categories (c) and<br>(d) who has put<br>atleast ten years<br>service. |
| (f) | Stenographer Grade I -<br>for the courts of Civil<br>Judge(J.D)/Judicial<br>Magistrates/C.J.M./<br>Additional C.J.M./<br>Civil Judge(SD)/<br>Additional Civil<br>Judge(SD) | Rs.4000-6000<br>or pay scale<br>refixed by<br>Government<br>from time to<br>time.   | By direct<br>recruitment   |
| (g) | Personal Assistants to<br>the courts of Additional<br>District & Sessions<br>Judges  | Rs.5500-9000<br>or pay scale<br>refixed by<br>Government<br>from time to<br>time.   | By promotion from<br>amongst the<br>category (f) having<br>five years<br>experience  |
| (h) | Personal Assistants to<br>the courts of District &<br>Sessions Judges.   | Rs.6500-10,500<br>or pay scale<br>refixed by<br>Government<br>from time to<br>time. | By promotion from<br>amongst the<br>category (g).  |

The categories mentioned at sub-clause (a) to (e) will form one cadre and categories (f) to (h) will be another cadre.

### FAMILY COURTS

S.No	Name of the post	Pay scale	Source of recruitment
(a)	Typist-cum-Copyist.	Rs. 3050- 4590 or pay scale refixed by the Government from time to time.	By direct recruitment
(b)	Assistant Accountant/ Execution Clerk-cum- Conservation Clerk, Suits Clerk-cum- Maintenance Clerk.	Rs. 4000-6000 or the pay scale refixed by the Government from time to time.	By promotion or on deputation from the Judgeships
(c)	Reader	Rs. 4500-7000 or the pay scale refixed by the Government from time to time.	By promotion or on deputation from the Judgeships.
(d)	Personal Assistant.	Rs.5500-9000 or the pay scale refixed by the Government from time to time.	By direct recruitment or on deputation from the Judgeships.

- (e) Sadar Munsarim      Rs. 5500-9000 By promotion or on  
or pay scale deputation from the  
refixed by Judgeships.  
Government  
from time to  
time.

**4. Sanctioned Strength of the Establishment :**

The strength of the ministerial establishment of a Judgeship or Family Court shall be such as may be determined by the Government from time to time.

**5. Nationality :**

No person shall be appointed to any ministerial establishment unless he be a citizen of India and registered in any Employment Exchange of Uttarakhand before publication of the advertisement by the commission.

**6. Academic Qualification:**

**Clerical Post:**

- (a) Must possess a Bachelor degree of University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto.
- (b) Must possess a thorough knowledge of Hindi and English.

- (c) Must possess good knowledge of Hindi and English typewriting having a speed of 40 words per minute on the computer.
- (d) Sufficient knowledge of operating computer.

**Stenographer & Personal Assistant of Family Courts:**

- (a) Must possess a Bachelor degree of a University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto.
- (b) Must possess a thorough knowledge of Hindi and English.
- (c) Must possess a speed of 80 and 100 words per minute in shorthand in Hindi and English respectively and typing 40 words per minute in Hindi and 60 words per minute in English.
- (d) Sufficient knowledge of operating computer.

**7. Age :**

A candidate for recruitment to a post in the ministerial establishment must have attained the age of twenty-one years and must not have attained the age of more than thirty-five years on the 1st day of January of the calendar year in which the vacancies for direct recruitment are advertised;



*Provided* that the upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified;

*Provided* the Chief Justice may extend the age limit in favour of a candidate on the grounds of public interest or fair dealing.

**8. Character :**

The character of a candidate for recruitment to a post in the ministerial establishment must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. He must produce a certificate of good character from the principal officer of the University or college or the school, as the case may be, in which he was last educated and from two responsible persons of status (not being relations), who are well acquainted with him in private life.

**Explanation -** Persons dismissed by the Union of Government or by any State Government or a Local authority or by a Corporation or body owned or controlled by the Union or any State Government shall be ineligible

for recruitment to the ministerial establishment. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

9. **Physical Fitness :** No person shall be appointed to the ministerial establishment unless he is in good mental and bodily health and free from all physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a person is appointed to any post, he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III .
10. **Reservation of Posts for Scheduled Caste etc.:** The Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of initial recruitment.
11. **Eligibility of Women:** Women are also eligible for appointment to the Establishment as per government orders in force.

12. **Marital Status :** A male candidate who has more than one wife living, or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to the ministerial establishment.

13. **PROCEDURE OF DIRECT RECRUITMENT TO THE SERVICE**

**Determination of Vacancies:**

- (a) Each District Judge and Principal Judge, Family Court in Uttarakhand shall ascertain the probable number of vacancies to be filled by direct recruitment during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies under rule 10 to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories in accordance with the orders of the State Government issued from time to time.
- (b) The vacancies will be notified and informed to the court.
- (c) The Court shall consolidate the vacancies so notified to it by the District Judges and the Family Courts, and it shall notify the vacancies to the Commission.

**(d) Competitive Examination :**

The competitive examination may be conducted at such time and on such dates as may be notified by the Commission.

**(e) Application Form :**

(1) Application for permission to appear at the competitive examination shall be invited by the Commission published in the advertisements issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

**(3) Fees-**

Candidates must pay to the Commission such fees as may from time to time be specified by the Government or the Commission. No claim for the refund of the fee shall be entertained.

(4) If the number of applicants is too excessive to the vacancies notified in the advertisement the Commission may conduct a preliminary entrance test in the manner prescribed by the Commission and the marks obtained in the preliminary test will



not be counted for determining the final order of merit.

**(5) Syllabus**

The competitive examination shall be held by the Commission as per the syllabus given in **Appendix-I.**

**(6) Canvassing**

No recommendation either written or oral other than those required under these rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate directly or indirectly may render him liable to disqualification.

(7) After the result of written examination is prepared, Commission shall call for interview such number of candidates, who in the opinion of the Commission, have secured minimum marks as may be fixed by the Commission.

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in any rules or orders, the Commission shall invite a person or an officer of the court to be nominated by the Chief Justice to participate in the interview of the candidates called under sub rule (7) and the opinion given by him with regard to the suitability by the Commission shall not be

overlooked unless there are strong and cogent reasons for not accepting the opinion for which reasons must be recorded in writing by the Commission.

**14. List of Candidates approved by the Commission :**

- (1) The Commission then shall prepare a select list of candidates in order of their merit as disclosed by aggregate of marks finally awarded to such candidates, in the written examination and the interview;

*Provided* that if two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate being elder in age, shall be placed higher in the select list ;

*Provided* that if two or more candidates of equal age obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate who has obtained higher marks in the written examination, shall be placed higher in the select list ;

- (2) The select list will be published by the Commission in the newspapers.

**15. Appointment to the Establishment :**

- (1) The select list (merit list) mentioning the aggregate marks obtained at the selection by each candidate so prepared by the Commission under rule 14 shall be forwarded to the court.
- (2) The Court shall send the names of the candidates to the District Judges and the Family Courts strictly in order of merit as per the vacancies in the Judgeships and the Family Courts. It would not be a right of any candidate for posting in the district of his choice.
- (3) The select list shall be valid for one year from the date of approval by the Chief Justice.
- (4) The District Judges and the Family courts shall make the appointments of the candidates whose names are sent by the Court as per the roster provided in government notification and orders.

**16. Registration of Selected Candidates :**

- (1) The names of candidates appointed by the District Judge and the Principal Judge, Family Court in accordance with Rule 15(4) shall be entered in order of merit in a bound register prescribed in Appendix II and each entry shall be initialed and dated by the District Judge or the Principal Judge, Family Court,

as the case may be, after inspection of the original attested copies of certificates.

- (2) The name of any candidate entered under sub-rule (1) may be removed for inefficiency or misconduct within a year without any departmental enquiry.
- (3) If any such candidate has not been given an appointment within one year from the date of recruitment, the list so recommended by the Commission shall stand lapsed. The candidate so recommended can not claim appointment to the establishment of Subordinate Civil Court and family courts.

*Provided* that any person aggrieved by any order under these rules or appointment made otherwise than in accordance with these rules or appointment purported to have been made under the rules, shall have a right to make a representation to the High Court of Uttarakhand.

#### **17. Probation :**

- (1) All persons on first appointment to the ministerial establishment except when the appointment is only in temporary or officiating capacity and on promotion to



higher posts that fall substantively vacant shall be on probation for a period of one year;

*Provided* that the District Judge or Principal Judge, Family Court, as the case may be, at his discretion extend the period of probation for a further period of six months.

- (2) The period of probation shall be counted from the date of taking over charge of the post.

*Explanation-* An appointee as a stenographer in ministerial establishment will also be put on probation for a period of one year.

- (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of period of probation that any person has not made sufficient use of his opportunities on promotion or if he has otherwise failed to give satisfaction, the District Judge or Principal Judge, Family Court as the case may be, may, without notice, revert him to his substantive post, if he holds one, or make any other suitable order.

- 18. Confirmation:** Subject to the provisions of the preceding rule, a probationer shall be confirmed against the permanent post.

**19. Seniority:** The Seniority of persons substantively appointed in the service shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

**20. Promotion :**

- (1) The higher post in a Judgeship or Family Court shall be reserved for clerks in that Judgeship or Family Court and promotion to higher posts shall be made from amongst them.
- (2) Except in cases of Amins, promotion shall be made according to seniority subject to efficiency.
- (3) Posts other than those mentioned in sub rule (2) above, shall be treated as selection posts, promotion to which shall be based on merit with due-regard to seniority, with a suitability test as prescribed by the District Judge or Principal Judge, Family Court, as the case may be.
- (4) The promotion from the lowest grade to the next higher grade shall be made if the persons have sufficient knowledge of Circular letters, General Rules (Civil and Criminal), Financial Hand Book after taking a suitability test by the District Judge and the Principal Judge, Family Court as prescribed by him.

- (5) The posts of Sadar Munsarim and Senior Administrative Officers are of promotional and of selection posts. The promotion to these posts will be made from amongst the persons who have sufficient knowledge of working in all departments of the Judgeship, particularly, the Nazarat and Accounts. While making the promotion to the posts of Sadar Munsarim and the Senior administrative Officer, the District Judge will conduct a suitability test as prescribed by him of the persons of working in the next lowest grade to these posts and then make promotion to these posts on the basis of merit-cum-seniority. The cases of senior Personal Assistants shall also be considered by the District Judge for the post of Senior Administrative Officer.
- (6) The Chief Justice, if he deems fit, may make appointment on the posts of Sadar Munsarim and the Senior Administrative Officer of the member of any Judgeship provided the vacancy exists in such judgeship.

**Note** - In passing over a person for inefficiency as well as promotion for a selection post due weight shall be given to his previous record of service and seniority should be disregarded only when the junior official

promoted is of outstanding merit as compared to his seniors.

- (7) In Courts subordinate to the High Court, promotions to the Amins from the second to the first grade shall, as a rule, be made within the local jurisdiction of a District Judge considering the ground of superiority of general qualifications, irrespective of length of service.
- (8) Promotions or appointments to the posts of Amins in subordinate Civil Courts shall ordinarily be confined to persons regarding whom the District Judge is satisfied that they have a sufficient knowledge of-
  - (i) Hindi and English.
  - (ii) Arithmetic.
  - (iii) Measurement.
  - (iv) Elementary land surveying and mapping.
  - (v) Code of Civil Procedure.
  - (vi) Rules in General (Civil) relating to the work and duties of the Amins;

*Provided* in exceptional circumstances the District Judge may exempt an official from such qualifications if he is satisfied that the official concerned is otherwise fit to hold the appointment.



- (9) An official once promoted to the post of Amin shall not, for purposes of promotion to other posts in general office be entitled to claim seniority by reasons of such promotion over other clerks who were senior to him before his promotion as Amin.
- (10) The appointment by way of promotion from the eligible candidates of group 'D' within the prescribed quota shall be made by the appointing authority in accordance with the conditions and procedure prescribed by rules and Government orders issued from time to time in the lowest pay scale of Group 'c'.
- 21. Scale of Pay :** The Scales of pay of persons appointed to posts in the cadre, whether in substantive or officiating capacity, or as a temporary measure shall be as sanctioned by the State Government from time to time.
- 22. Pay During Probation :** The pay during probation of a person directly recruited shall be the minimum pay of the post to which he is appointed and in the case of a person already in the service of the State it shall be such as may be admissible to him under the relevant rules referred to in rule 21. Increments will be earned by approved probationary service provided that if, in any case the period of probation is extended on account of failure to give

satisfactory service, such extended period shall not be counted for increment.

**23. Transfers :**

(1) The Chief Justice may transfer any Sadar Munsarim or any Senior Administrative Officer or any member of the establishment from any Judgeship to another Judgeship in the same pay scale against existing vacancy on the complaint of the District Judge or in the public interest.

(2) The District Judge may transfer any member of the establishment within the District in the same pay scale from one court/office/department to another, as he deems fit.

**24. Applicability of Dying in Harness Rules :**

Notwithstanding any thing to the contrary contained in these rules the Uttarakhand (Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servant Dying in harness Rules, 1974) Adaptation & Amendment Rules, 2002 shall be applicable to the ministerial establishment. Recruitment will be made by the appointing authority accordingly.

**25. Repeal & Savings :**

(1) The Subordinate Civil Court Ministerial Establishment Rules 1947 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal :

- (a) If immediately before the date on which these rules come into force, there is any matter pending regarding salary, pension, seniority, disciplinary action or other connected matters shall be disposed of in accordance with the provisions of the Subordinate Civil court Ministerial Establishment Rules, 1947.
- (b) All notifications and circular letters of the High Court or of the State Government, if any, issued under the Subordinate Civil Court Ministerial Establishment Rules, 1947, shall be deemed respectively to have been issued under the corresponding provisions of these rules.

By order  
*R.D. Paliwal*  
( R.D. PALIWAL )  
Secretary

**Appendix I**  
**(Vide Rule 13)**

The examination shall be in three parts.

<b>(1) Written Test:</b>	<b>Marks</b>
(i) Simple drafting (in Hindi)	40
(ii) Essay and Precise Writing (in Hindi)	40
(iii) Simple drafting and Precise Writing (in English)	40
(iv) General Knowledge	40
<b>(2) Test in Typewriting on computer/ Shorthand Writing</b>	<b>60</b>

**For Stenographers:**

- (i) Type writing in English and Hindi on the Computer having a speed of 60 words per minute in English and 40 words per minute in Hindi.
- (ii) Shorthand writing in English with a speed of 100 words per minute and in Hindi with a speed of 80 words per minute.

**For others:**

Type writing in English and Hindi having a speed of 40 words per minute on the computer.

<b>(3) Interview</b>	
(i) Personality	15
(ii) Knowledge and suitability for the particular post	15
<b>Total Marks-</b>	<b>250</b>



**Appendix II**  
**(Vide Rule 16)**

**Form of Register of Recruited Candidates.**

Name	Father's Name	Caste Religion class, if from reserved class	Address Permanent and temporary	Date of birth & Age	Academic Qualifications	Year & position After written Test and Interview	Special Qualification e.g., Stenography Accounts etc.
1	2	3	4	5	6	7	8

By order

*R.D. Paliwal*

( R.D. PALIWAL)

Secretary